.विकास पर मंथन. बिहार ग्रोथ कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन स्वास्थ्य सहित कई विषयों पर हुई चर्चा

# स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जरूरी

संवाददाता ▪ पटना

इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के बिहार ग्रोथ कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना के साथ ही कई मामलों में राष्ट्रीय औसत से कम होने पर चिंता भी जतायी गयी. गुरुवार को 'स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास-चुनौतियां व अवसर' विषय पर सेमिनार में विशेषज्ञों ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने पर बल दिया.

## कर्नाटक में बदली तसवीर

कर्नाटक सरकार के एनआरएचएम के मिशन डायरेक्टर एस सेल्वा कुमार ने अपने राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कार्यों को ब्योरा प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में समेकित स्वास्थ्य सूचना तंत्र विकसित किया गया. बीमारियों के अनुसार इलाज का तंत्र विकसित किया गया. एक समय कर्नाटक में डॉक्टरों की उपस्थिति 40 प्रतिशत, नर्स की 60, तो क्लर्क की बमुश्किल 25 प्रतिशत तक ही थी. तब स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन पर काम शुरू किया गया. हर मरीज का डाटा बीमारी के अनुसार संग्रह किया जाने लगा. उपस्थिति बढ़ाने के लिए डिजिटल विधि व फिंगर प्रिंट से हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया. पांच जिलों व 140 पीएचसी से इसकी शुरुआत हुई. कर्मियों के अवकाश की निगरानी शुरू हुई. मुख्यालय में एक सर्वर लगाया गया, जो हर पीएचसी की अद्यतन स्थिति बताया करता. स्वास्थ्य सेवा में तबादले के लिए अक्सर राजनीतिक दबाव रहता है. इसके लिए एक नियमावली बनायी गयी कि कम-से-कम छह साल की सेवा के बाद ही अर्द्धशहरी व फिर शहरी क्षेत्र में पदस्थापित किया जायेगा. दवाओं के भंडारण के लिए इ-प्रॉक्यूरमेंट सिस्टम अपनाया गया. दवाओं की आवश्यकता के अनुसार उसकी खरीद की गयी. इसका नतीजा यह हुआ कि 2009-10 में प्रति यूनिट 283 रुपये से 2011-12 में यह घट कर 137 रुपये प्रति यूनिट तक आ पहुंचा है. वित्तीय प्रबंधन सिस्टम को दुरुस्त किया गया. एसबीआइ से करार किया गया और पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाने लगा. पीएचसी में कंप्यूटर दिये गये और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया. मोबाइल वैन शुरू किये गये, जिसमें डॉक्टरों की टीम रहती है. नर्स को मोबाइल दिया गया. गर्भवती मरीजों के अस्पताल में आते ही एसएमएस से उनका पंजीकरण किया गया. जरूरतमंदों को तीन घंटे में खून उपलब्ध कराने के लिए रक्तवाहिनी चलायी जा रही है. आम लोगों को सरकार की ओर से उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इसके लिए थर्ड पार्टी से इसका मूल्यांकन कराया गया.

आइजीसी कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रखते संजीवन सिन्हा. फोटो । प्रभात खबर

**बीमारियों के अनुसार इलाज का तंत्र विकसित किया गया : एस सेल्वा**

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण एक क्रांतिकारी कदम : संतोष

**12वीं योजना का एप्रोच पेपर बनाने में मिलेगा सहयोग : विजय प्रकाश**

जीविका से राज्य की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन : विजयेंद्र

**पांच साल में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में होगा गुणात्मक सुधार : संजय**

टीकाकरण अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण : रंजन

## स्वयं सहायता समूह से सफलता

विश्व बैंक से आये अर्थशास्त्री विजयेंद्र राव ने बिहार में चल रहे जीविका पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. सात जिलों, 179 पंचायतों व 8950 घरों में किये गये सर्वे के आधार पर राव ने कहा कि जीविका कार्यक्रम बिहार के लिए काफी मायने रखता है. संख्या, गुणवत्ता व प्रयोग के आधार पर किये गये सर्वे से यह उभर कर आया कि जीविका से बिहार में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं. स्वयं सहायता समूह के प्रयास से यह कार्यक्रम और सफल हुआ है.

## महिला आरक्षण क्रांतिकारी कदम

यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के संतोष कुमार व यूनिवर्सिटी ऑफ केनेटिकल, अमेरिका के असिस्टेंट प्रोफेसर निशीथ प्रकाश ने बिहार में महिलाओं को आरक्षण और बच्चों के स्वास्थ्य विषय पर अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया. नीतीश सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिये जाने को क्रांतिकारी कदम बताते हुए संतोष कुमार ने कहा कि यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है. महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत, तो राजनीति में मात्र 18.4 प्रतिशत ही महिलाओं की भागीदारी है.

ऐसे में बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिलने से समाज में व्यापक क्रांति आयी है. सर्वे में यह उभर कर आया कि महिलाएं सम-सामयिक मुद्दों को लेकर अधिक गंभीर रहती हैं. पंचायत के सशक्त होने से स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हो रहा है. बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण देते हुए श्री कुमार ने कहा कि संस्थागत प्रसव, शिशु मृत्यु दर व अन्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है. डिमांड की खोज हो और फिर उसी के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम हो. बिहार सरकार के बेहतर परफॉरमेंस के पीछे वक्ता ने साइकिल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एनआरएचएम को भी एक कारण बताया.

## टीकाकरण औसत से अधिक

राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार ने कहा कि सरकार के अन्य विभागों की तुलना में स्वास्थ्य का अलग स्थान है, स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं बनायी हैं. शेखपुरा में मोबाइल के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जा रहा है. छह और जिलों में इसे शुरू किया जायेगा. संपूर्ण टीकाकरण में बिहार का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है. पंचायत स्तर तक पॉलिटिकल ऑनरशिप ली जाये.

केयर इंडिया-बिहार के सुजीत रंजन ने टीकाकरण अभियान में स्वयं सहायता समूह की अहम भूमिका बतायी. बेंगलुरु से आयी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सुनीता कृष्णन ने खून की कमी के शिकार मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जतायी.

## सेमिनार से लाभ होगा

सत्र की अध्यक्षता करते हुए योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने कहा कि आइजीसी के इस सेमिनार से बहुत लाभ होगा. 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एप्रोच पेपर तैयार किया जा रहा है.

# बिहारी होना गर्व की बात : मोदी

संवाददाता ▪ पटना

बिहार के विकास को लेकर दो दिनों तक चले गहन चिंतन-मनन और मार्ग की तलाशने की क्वायद कर देश-विदेश के अर्थशास्त्री, नीति निर्धारक व प्रशासक गुरुवार को विदा हो गये. आइजीसी व आद्री की इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह पर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि हम ऐसा बिहार बनायेंगे कि बिहारी होना गर्व की बात होगी. अब लोग बिहारी होना गर्व की चीज मानते हैं. हम धीरे- धीरे चीजें सुधार रहे हैं. वे समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे. पैनल में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा व मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री पीके शाही मौजूद थे. वहीं समारोह में अर्थशास्त्री व बुद्धिजीवियों ने पैनल से कई सवाल पूछे. समापन समारोह पर आइजीसी भारत बिहार कार्यक्रम के निदेशक प्रो अंजन मुखर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

## अमरजीत सिन्हा ने कहा

- 40 साल बाद बिहार में एक मेडिकल कॉलेज में नामांकन शुरू हुआ है.
- आजादी के बाद बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हमने आइजीआइएमएस व कुर्जी हॉस्पिटल में स्थापित की है.
- यहां सिविल सर्जन व डॉक्टर को आज 20 राज्यों की तुलना में सबसे अधिक वेतन दिया जा रहा है.
- स्वास्थ्य कार्यक्रम की वजह से जहां शिशु मृत्यु दर में कमी आयी, वहीं सामान्य मृत्यु दर में भी कमी आयी है.

हम शिक्षा में सुधार के लिए पहल कर रहे हैं. हमने काफी स्तर तक कार्य किया है. हमारे प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा इसी बात का सबूत है. भविष्य में हमें इसके लिए और बेहतर प्रबंधन करना है.

**पीके शाही**, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार

# कॉमर्शियल टैक्स की स्थिति सुधारे बिहार

संवाददाता ▪ पटना

बिहार से ही अलग हुए राज्य ओड़िसा में कॉमर्शियल टैक्स जमा करनेवालों की स्थिति बेहतर है. 1.4 लाख छोटे डीलर्स ओड़िसा में कॉमर्शियल टैक्स जमा करते हैं, जबकि बिहार में केवल 48 हजार छोटे डीलर्स ही कॉमर्शियल टैक्स जमा करने में रुचि लेते हैं. सूबे में इसका नतीजा यह है कि हम अर्थव्यवस्था में विकास करने के बावजूद राज्य में बेहतर आधारभूत संरचना नहीं विकसित कर पा रहे हैं. यह जानकारी विश्व बैंक के राजुल अवस्थी ने दी. उत्तरप्रदेश में कॉमर्शियल टैक्स जमा करने की संख्या और भी सुदृढ़ है. यहां चार लाख लोग कॉमर्शियल टैक्स जमा करते हैं.

## खास तथ्य:

- बिहार में 80 प्रतिशत कॉमर्शियल टैक्स राजधानी से मिलता है.
- बिहार के विकास में 75 फीसदी विकास केवल राजधानी का है.
- अन्य स्टेट में भी ऐसे ही आंकड़े हैं, लेकिन बिहार में यह सबसे ज्यादा है.
- ऐसे आंकड़े एकांगी विकास की ओर इशारा करते हैं.
- बिहार की मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीएसपी) 9.7 है.
- जबकि सभी राज्यों की कुल 8.7 है.
- बिहार में जीडीएसपी की कर राजस्व 4.8 प्रतिशत है, जबकि कर्नाटक में यह 8.7 है.
- वर्ष 1981 से 1994 तक हमारी जीडीएसपी 3.6 थी, वहीं सभी राज्यों की 4.6

## क्यों हो रहा ऐसा

- जिला स्तर पर टैक्स प्रशासन कमजोर है.
- सभी जिलों के लोग राजधानी में खर्च करते हैं.
- इस खर्च का टैक्स नहीं पेय हो रहा है.
- बाजारों का जिस तरह से फैलाव होना चाहिए, वह अभी कम है.
- सूचना तंत्र कमजोर है.
- कोई आधारभूत मजबूत संरचना नहीं है.

## क्या हैं सुझाव

- टैक्स सिस्टम को ठीक करना होगा.
- लोगों को जागरूक करना होगा.
- सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा.
- छोटे डीलर्स की पहचान करनी होगी.
- प्रशासन इनसे अधिक से अधिक डीलर्स से कॉमर्शियल टैक्स ले.
- आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की सहायक प्राध्यापक डॉ चिरश्रीदास गुप्ता ने अपने शोध पत्र में ये बातें रखी. उन्होंने सुझाव के तौर पर कहा कि इन सुझावों के जरिये कॉमर्शियल टैक्स में बिहार अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है.

# रोजगारपरक शिक्षा से बदलेगी तसवीर

**पटना :** इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर की ओर से आयोजित बिहार ग्रोथ कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन विशेष व्याख्यानमाला में वक्ताओं ने शिक्षा व टैक्स इंस्पेक्टरों की ओर से किये जानेवाले राजस्व संग्रहण पर अपना पक्ष रखा. देश-दुनिया के संदर्भ में बिहार की तुलना की और समस्याओं का समाधान बताया.

## आर्थिक रूप से कमजोर को मिले आरक्षण

आइएसआइ, कोलकाता के अभिरूप सरकार ने कहा कि आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलनी चाहिए. रोजगारपरक शिक्षा होनी चाहिए. पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, देश में सबसे अधिक खर्च यह राज्य प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च करता है. इस मामले में खर्च होने का प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 44.7, तो राष्ट्रीय औसत 40 प्रतिशत है. पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का स्थान है. हालांकि, अनुसूचित जाति के लोग प्राइवेट ट्यूशन पर कम खर्च करते हैं. इस स्थिति से उबरने का एक ही उपाय है कि पिछड़ों को शिक्षा के लिए सरकार अनुदान दे.

## समस्याओं को चिह्नित कर हो उनका निदान

पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अदनान खान ने 147 टैक्स इंस्पेक्टरों पर किये गये सर्वे की रिपोर्ट पेश की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो या भारत या फिर बिहार, टैक्स इंस्पेक्टरों की कार्यशैली, समस्या या निदान एक जैसा ही है. राजस्व संग्रह में कमी का कारण टैक्स इंस्पेक्टरों का कम वेतन, बुनियादी सुविधाओं की कमी व इनसेंटिव नहीं मिलने की बात आयी. उन्होंने कहा कि परफॉरमेंस इवैल्यूएशन कमेटी बननी चाहिए, जो शीर्ष, मध्यक्रम व निम्न स्तर को चिह्नित करे और उसका निदान उसी के अनुरूप हो. काम करनेवालों के जिम्मेवारियों को और बेहतर करने के लिए नये-नये प्रयोग हो.

# कर प्रशासन को सुदृढ़ करने की जरूरत

संवाददाता ▪ पटना

आइजीसी के तीसरे सत्र की शुरुआत राजकोषीय नीति व वित्त प्रबंधन को लेकर हुई. सत्र में सबसे पहले बिहार में समावेशी विकास विषय पर विशेष व्याख्यान आर्थिक सलाहकार समूह के सदस्य एम गोविंद राव ने दिया. अध्यक्षता वित्त विभाग के सचिव(व्यय) मिहिर कुमार ने की.

## शोध पत्र का सार

बिहार में राजकोषीय नीति व कर प्रशासन में काफी कमियां है जिन्हें सुदृढ़ किये जाने की जरूरत है. समावेशी विकास संभव हो इसलिए जीडीपी में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य में खर्च के प्रतिशत को और अधिक करना होगा.

## सुझाव

- मजबूत राजकोषीय नीति से ही समावेशी विकास संभव
- विकास में कमजोर लॉ एंड ऑर्डर व कमजोर सरकार बाधा है. इसे मजबूत करे.
- राजनैतिक व आर्थिक स्थिरता जरूरी है.
- प्रशासन अपनी सर्विस को निचले स्तर तक ले जाये.
- आधारभूत संरचना और मजबूत करने की जरूरत.
- केंद्रीय नीति व फंड का राज्य में पूर्ण उपयोग जरूरी.
- मानव सूचकांक को मजबूत करें.
- शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश हो.

## ऊर्जा के क्षेत्र में ध्यान दें

इसके शोध पत्र के बाद नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के डॉ संजय बनर्जी ने वित्तीय मध्यस्थता और बिहार का आर्थिक विकास विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया. पिछले पांच वर्षों से बिहार में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है लेकिन ऋण जमा अनुपात बिल्कुल ठीक नहीं है. पावर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत ही कम है, इस पर ध्यान देना चाहिए.

## संसाधनों को बढ़ाएं

इस के बाद आंबेडकर विवि दिल्ली की डॉ चिरश्री दास गुप्ता ने कहा कि टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत है. वहीं वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव राजित पुनहानी ने सर्वाधिक उपयुक्त कर दरों के निर्धारण के लिए कर सुधारों और आंकड़ों के बेहतर ढंग से संग्रह संकलन की बात कही.

## बिहार ग्रोथ कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन विशेषज्ञों ने कहा

# बने सिस्टम, हो निगरानी

इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर व आद्री का दो दिवसीय बिहार ग्रोथ कॉन्फ्रेंस के पहले दिन देश-विदेश के अर्थशास्त्रियों, शिक्षाशास्त्रियों और प्रबंधन व प्रशासन के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों ने बिहार के विकास के लिए जल, जमीन व ज्ञान (शिक्षा) पर जोर दिया था. दूसरे दिन गुरुवार को उन्होंने तकनीक आधारित नियंत्रण व निगरानी प्रणाली अपनाने की सलाह दी. इसके लिए देश-विदेश के कई सफल मॉडलों पर किये गये शोध को दिखाया गया. उनका कहना था कि वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा, जल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं को जनोपयोगी व प्रभावी बनाने के लिए देश-दुनिया में तंत्र विकसित किये गये हैं, ऐसा तंत्र अगर बिहार विकसित कर ले, तो यहां विकास की गति कई गुनी तेज हो जायेगी.

### स्वास्थ्य सेवा

- डिजिटल व फिंगरप्रिंट से अस्पतालकर्मियों की बने हाजिरी
- समेकित सूचना तंत्र व बीमारियों की निगरानी का सिस्टम विकसित हो
- दवाओं की खरीद, अस्पताल में आनेवाले मरीजों व बीमारियों का डाटा संग्रह अत्याधुनिक तरीके से हो
- स्वास्थ्यकर्मियों के तबादले की प्रभावकारी नीति बने.
- स्वयं सहायता समूह से ली जाये मदद
- निचले स्तर पर भी राजनीतिक नेतृत्व तय हो

### वित्तीय प्रबंधन

- टैक्स के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चले
- टैक्स में वृद्धि के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल हो
- सभी क्षेत्रों में खर्च की दर बढ़ायी जाये
- शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी अधिक हो
- जिला स्तर पर टैक्स प्रशासन को मजबूत किया जाये

संबंधित खबरें पेज दो पर

स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी तंत्र का अधिक इस्तेमाल हो. एक नागरिक हेल्प डेस्क बनाया जाये, जहां लोग बीमारी के बारे में सूचना ले सकें.

**एस सेल्वा कुमार**, मिशन डायरेक्टर, एनएचआरएम, कर्नाटक

राजस्व में वृद्धि के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है. स्थानीय स्तर पर कर प्रशासन को अपने तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है.

**एम गोविंद राव**, सदस्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार

निचले स्तर पर प्रभावी निगरानी की जरूरत है. पंचायतों की अहम भूमिका हो सकती है. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण क्रांतिकारी कदम है. इससे समाज में व्यापक बदलाव आया है.

**संतोष कुमार**, वाशिंगटन विवि

बिहार में केवल 48 हजार छोटे डीलर ही कॉमर्शियल टैक्स जमा करने में रुचि लेते हैं. इसका नतीजा यह है कि हम अर्थव्यवस्था में विकास करने के बावजूद राज्य में बेहतर आधारभूत संरचना नहीं विकसित कर पा रहे हैं.

**राजुल अवस्थी**, विश्व बैंक

# सूबे में तेज होगी विकास की गति

पटना (एसएनबी)। सूबे में विकास की गति और तेज की जाएगी। छह वर्ष पहले एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास की नींव डाली थी, जो आज रफ्तार पकड़ चुकी है। ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बृहस्पतिवार को आईजीसी व आद्री द्वारा आयोजित दो दिवसीय बिहार ग्रोथ सम्मेलन के समापन सत्र में कही।

मोदी ने कहा कि आज माहौल बदल गया है। राज्य में विकास की गति काफी बढ़ी है। चाहे वह कृषि, स्वास्थ्य, सड़क हो या फिर शिक्षा। अब राज्य के गांव-गांव की सड़कें काफी बेहतर हो गयी हैं। यहां कई मार्गों को फोर लेन में तब्दील किया जा रहा है। अब किसी भी जिले से राजधानी महज छह से सात घंटे में सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी बदलाव हुआ है। राज्य में गंगा, कोशी आदि नदियों पर नए सेतु बनाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने कहा कि सूबे में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 28 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। छह साल पहले स्कूलों में लड़कियों की संख्या काफी कम थी लेकिन आज वे दो-चार किलोमीटर चलकर शिक्षा ग्रहण करती हैं। इस बार भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लड़कियां टॉप पर रही। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा ने कहा कि सरकार कई मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। आईजीआइएमएस में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दी गयी है। अब सदर अस्पतालों में हर रोग के चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की कवायद चल रही है। सम्मेलन के आखिरी दिन भी कई सत्र चले। इसमें वित्त विभाग के सचिव संजीवन सिन्हा, कोलकाता के अर्थशास्त्री डॉ. अभिरूप सरकार, पाकिस्तान के शोध नेटवर्क निदेशक अदनान खान, योजना व विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश, एस सेल्वा कुमार, विजेन्द्र राव, वाशिंगटन विवि के टीचर संतोष कुमार, राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक संजय कुमार, सुजीत रंजन, सुनीता कृष्णन, वित्त विभाग के सचिव मिहिर कुमार, एम गोविंद राव ,डॉ. चिरश्री दास गुप्ता, अंजनी कुमार वर्मा न ने भी विचार रखे।

*आएगी खुशहाली :* सम्मेलन को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी व अन्य।

## आईजीसी बिहार ग्रोथ सम्मेलन

▶ अब बदल गया प्रदेश का माहौल : मोदी

# बिहार के विकास में केन्द्रीय सहायता अनिवार्य

- प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही प्राथमिकता : उपमुख्यमंत्री
- शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण विकास पर जोर : पीके शाही

पटना, हमारे संवाददाता : ''बिहार ने कई क्षेत्रों में निश्चित रूप में प्रगति की है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन समेत कुछ अन्य सेक्टर हैं, जहां काफी काम हुआ है। शासन तंत्र में काफी बदलाव आया है। मगर राज्य सरकार को योजनाओं की प्लानिंग कुछ इस तरह करनी चाहिए, ताकि उसमें केन्द्रीय सहायता और सहयोग का स्कोप ज्यादा से ज्यादा हो।'' यह 'आइजीसी बिहार ग्रोथ कांफ्रेंस-2011' के बैनर तले यहां जुटे देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय का निष्कर्ष है।

सम्मेलन में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और पाकिस्तान से कुल 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत के चार दर्जन से अधिक प्रतिनिधि थे। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अंतिम सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमें बिहारी होने पर गर्व है। मगर हम प्रदेश का इस तरह से समुचित विकास करेंगे कि हमें देश-दुनिया में कहीं भी बिहारी कहलाने पर गर्व महसूस होगा। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने शैक्षणिक उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा के अनुसार, चिकित्सकों की नियुक्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर सभी अस्पतालों में संपूर्ण सुधार लाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आइजीसी के निदेशक अंजन मुखर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव रजित पुनहानी एवं अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किये।

## केन्द्रीय सहायता अनिवार्यः अभिरूप सरकार

जाने-माने अर्थशास्त्री अभिरूप सरकार ने कहा कि यहां पैदावार वाली कृषि योग्य पर्याप्त भूमि है। कृषि क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं, किंतु विकासशील प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता अनिवार्य है। जल संसाधन के लिए केन्द्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

## प्रदेश में दिख रहा विकास कार्य : विजेन्द्र राव

विश्व बैंक के विशेषज्ञ विजेन्द्र राव ने बिहार में हो रहे विकास के प्रयास को सराहा। बातचीत में उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में इस प्रदेश में शासन तंत्र बेहतर हुआ है और इसकी बदौलत कई क्षेत्र में विकास के कई नये आयाम दिखने लगे हैं।

## 'स्वास्थ्य से जुड़े ग्रामीण विकास'

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के संतोष कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने की चुनौतियां भी हैं। कर्नाटक सरकार के सीनियर अफसर एस.सेल्वा कुमार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एचआइवी/एड्स पर भी काम करने पर जोर दिया।

दो दिनों का आइजीसी बिहार ग्रोथ कांफ्रेंस बिहार की चुनौतियों व समाधान पर बात करते हुए गुरुवार को समाप्त हो गया। कांफ्रेंस में आये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने खासकर ऊर्जा उत्पादन, राजस्व वसूली, भूमि व कृषि में सुधार और योजनाओं के क्रियान्वयन में कुशलता लाने के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।